

2029 तक उप्र की अर्थव्यवस्था होगी एक ट्रिलियन डालर, देश में होगी सबसे बड़ी

विधानसभा में **मुख्यमंत्री** योगी ने कहा-प्रदेश की विकास दर देश में सबसे उत्तम

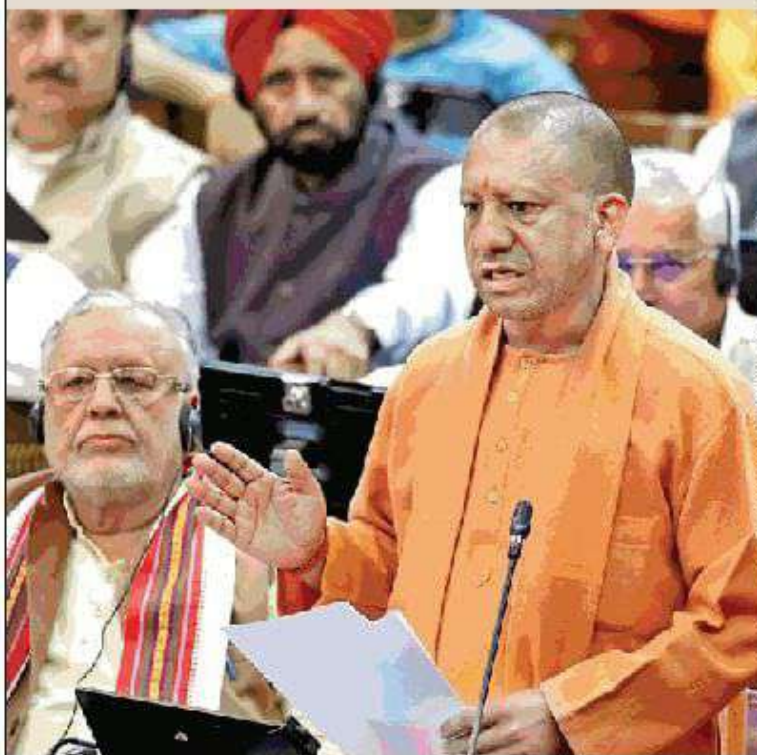
राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उप्र की विकास दर सबसे अच्छी है। जब उनकी सरकार आई थी, तब उप्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12 लाख करोड़ रुपये था, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.50 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार एक ट्रिलियन डालर हो जाएगा।

योगी सभा सदस्य डा. रागिनी सोनकर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे जिन्होंने पूछा था कि सरकार ने एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है? मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि पर भी सवाल उठाते रहते हैं। भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि जिनका अपना निजी एजेंडा होता है, वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच चुकी है। वर्ष 2027 तक भारत पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्य नहीं करना चाहता हूं कि वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी

• अकेले महाकुंभ के आयोजन से अर्थव्यवस्था में होगी तीन लाख करोड़ रुपये की वृद्धि

• प्रदेश की आर्थिकी को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को सरकार ने किया चिह्नित



विधानसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • सुषमा विभाषा

सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और वह अपने स्तर पर त्रिमासिक समीक्षा करते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। कई उद्योगों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इस निवेश से

60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र आज देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयों संचालित करने वाला राज्य बन चुका है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह सेक्टर बर्दाहल हो गया था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया। इससे दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। सीएम युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है जिसके तहत पांच लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है। योजना के पहले

2023 के बाद से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है

किसानों को मिल रहा लागत का डेढ़ गुणा मूल्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हालत वर्ष 2017 से पहले बेहद खराब थी। आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, बल्कि अपनी उपज का डेढ़ गुणा मूल्य पा रहा है। उन्होंने बताया कि धान की खेती में किसानों को



प्रति क्विंटल 2300 रुपये मिल रहे हैं, जबकि लागत 1100 रुपये आती है। इसी तरह गेहूं पर भी सरकार किसानों को दोगुना मूल्य दे रही है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान मिल रहा है।

चरण में पांच लाख रुपये और दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। अब तक 96 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2023 में 65 करोड़ पर्यटक राज्य में आए और महाकुंभ में अकेले 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होगी।

पंथायत चुनाव को 'खेत' तैयार, सरकार ने दी योजनाओं की 'खट' » पेज 11